जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

Rashtradoot

फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 96 प्रभात जयपुर, गुरूवार 5 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

भारत के लिए क्या मायने हैं, अमेरिका के चुनाव नतीजों के?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डैमोक्रैटिक पार्टी की जीत को भारत काफी हद तक सकारात्मक रूप से देख रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। मंगलवार को हुए अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है और भारत पर इसके प्रभाव को काफी हद तक सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है।

- व्यापार और आयात शुल्क पर ट्रंप के साथ भारत का विवाद चल रहा है। ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर कई भारी शुल्क लगाए गए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
- भारत उम्मीद कर रहा है कि डैमोक्रैटिक पार्टी के वर्चस्व वाली अमेरिकी कांग्रेस इन शुल्कों के नकारात्मक प्रभाव की गहराई से जाँच करेगी और संभवतया इन पर अंकुश भी लगाएगी।

टैक्सस, ओहायो, कंसास, आयोवा, नॉर्थ कैरोलाइना, साउथ कैरोलाइना और मेन में सीटें जीतने के बाद, डेमोक्रेट्स को सीनेट में कम से कम 54 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, प्रतिनिधि सभा में भी दो दर्जन से अधिक सीटें जीतकर उन्होंने आरामदायक बहुमत हासिल कर लिया है। नई कांग्रेस जनवरी 2027 में कार्यभार संभालेगी। इससे डेमोक्रेट्स को कानून बनाने, धन आवंटित करने, जांच करने और सरकारी कामकाज पर निगरानी रखने के अधिक अधिकार मिलेंगे। हालांकि, ट्रंप के पास अब भी किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार है और कार्यपालिका की व्यापक शक्तियां बनी रहेंगी।

व्यापार और आयात शुल्क ट्रंप प्रशासन के साथ विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए शुल्कों से भारतीय निर्यात में कई अवरोध आ गए थे। कुछ वस्तुओं पर ये शुल्क पहले 50 प्रतिशत तक पहुंच गए थे, लेकिन बाद में एक अंतरिम व्यवस्था के तहत घटकर लगभग 18 प्रतिशत रह गए। उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक कांग्रेस इन शुल्कों से अमेरिकी कारोबारियों और उपभोक्ताओं को होने वाले आर्थिक नुकसान की अधिक गहराई से जांच करेगी। संभवतः इस मुद्दे पर बहस और सुनवाई हो सकती है, जो भारत पर दबाव कम कर सकती है या फिर एकतरफा तरीके से शुल्क और बढ़ाने की कोशिशों को मुश्किल बना सकती है। व्यापक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। कृषि बाजार तक पहुंच और भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों के कारण भी इसमें अड़चनें हैं। अब इस समझौते की कांग्रेस में अधिक समीक्षा हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि डेमोक्रेट्स ने ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे के लिए बाजार खोलने की नीति का समर्थन किया है। इसलिए भारत को राहत मिलना तय नहीं है, लेकिन सत्ता का बदला हुआ संतुलन संरक्षणवादी नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिशों को धीमा कर सकता है।

एच-1बी वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी अब अधिक विवाद होने की संभावना है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ नए एच-1बी आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे अदालतों में पहले ही

(शेष पृष्ठ 6 पर)

नेतन्याहू व ट्रंप की कहानी दोहराई जाएगी भारत में?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। एक समय की बात है, तीन गहरे दोस्त हुआ करते थे।

इनमें सबसे पहले जिसकी कुर्सी छूटी और जो मुश्किलों में फंसा, वह था इज़रायल का बेंजामिन नेतन्याहू। इसके

- कांग्रेस ब्लॉक चाहता तो यह ही है, पर, अभी तक तो यह केवल रोचक कहानी ही है।

बाद डॉनल्ड ट्रंप की बारी आई, जिन्हें अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। अब उनके लिए अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

यह डेमोक्रेट्स की जबरदस्त लहर है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी को मतदाताओं ने सत्ता से बाहर कर दिया है और दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो गया है।

आने वाले राजनीतिक संकट के संकेत पहले से ही साफ थे। ट्रंप बड़ी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

अग्निवीर प्रोग्राम वापस होगा?

अग्निवीर योद्धाओं का कार्यकाल दो साल और बढ़ाया गया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। केन्द्र सरकार ने बुधवार को "अग्निवीरों" के कार्यकाल में दो साल की बढ़ोतरी की घोषणा की। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

वर्ष 2022 में शुरू की गई "अग्निपथ योजना" के तहत, सशस्त्र बलों में कम अवधि के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में जवानों की औसत आयु कम करना है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को "अग्निवीर" कहा जाता है।

मंत्रिमंडल का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सशस्त्र सेनाओं में करीब 18,000 अग्निवीरों का सशस्त्र बलों में कार्यकाल समाप्त होने वाला था।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवसर उनके प्रदर्शन और उसकी समीक्षा पर निर्भर करेगा।

जनरल सुब्रमणि ने कहा, "शुरुआत से ही यह स्पष्ट था कि इस योजना की समीक्षा की जाएगी। हर साल अग्निवीरों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और इसके बाद हमने दो साल का कार्यकाल विस्तार देने का फैसला किया।"

अग्निपथ योजना के तहत, सैनिकों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की जाती थी तथा इनमें से केवल 25 प्रतिशत को ही नियमित सैन्य सेवा में बनाए रखने का प्रावधान था।

- वर्ष 2022 में शुरु की गई अग्निवीर योजना का उद्देश्य सेना के जवानों की औसत आयु कम करना था। इस योजना में चार साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती है। इन सैनिकों को ही अग्निवीर कहा जाता है।
- सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब 18,000 अग्निवीर रिटायर होने वाले हैं और इससे चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता था।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में सेवा जारी रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

'भारत को होर्मुज़ से गुज़रने की छूट है'

ईरान के एक वरिष्ठ संसदीय अधिकारी ने कहा कि भारत उन चार देशों में से एक है, जिन्हें होर्मुज़ से गुज़रने की छूट है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज़ स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) से जहाजों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से भारतीय जहाजों को छूट दी गई है। ईरानी संसद की एक समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पुष्टि की है कि भारत, चीन, इराक और कतर के जहाज बिना किसी पाबंदी के इस जलमार्ग से गुजर सकते हैं।

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अहमद हयात-मोगद्दम ने कहा कि चार देशों को यह छूट दी गई कि उनके जहाज होर्मुज़ से अपनी आवाजाही जारी रख सकते हैं।

ईरान की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक में हयात-मोगद्दम ने कहा कि

- ईरानी संसद की नेशनल सिक्युरिटी एण्ड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के वाइस चेयरमैन अहमद हयात मोगाद्दम ने कहा कि भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को होर्मुज़ से गुज़रने की छूट दी गई है।
- उन्होंने कहा, भारत को छूट इसलिए दी गई है, क्योंकि ईरान, भारत से दवाओं का आयात करना चाहता है।

भारत को छूट देने का फैसला तेहरान की दवाओं के आयात की जरूरत से जुड़ा है।

उन्होंने चीन के राजनीतिक समर्थन और ईरान के साथ उसके वित्तीय संबंधों को भी चीन को दी गई इस छूट के पीछे एक कारण बताया।

उन्होंने कहा, "होर्मुज़ स्ट्रेट के मामले में हमने पहले ही चार देशों को "माफ" कर दिया है। फिलहाल ये देश भारत, चीन, इराक और कतर हैं। वे स्वतंत्र हैं, यानी हमारी ओर से उन्हें छूट है। अमेरिकियों को भी उनके आने-जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनके जहाज होर्मुज़ स्ट्रेट से लगातार आते-जाते हैं।"

भारत के साथ इस व्यवस्था के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हमने भारतीयों के लिए ऐसा इसलिए किया है, ताकि हम दवाओं का आयात कर सकें।"

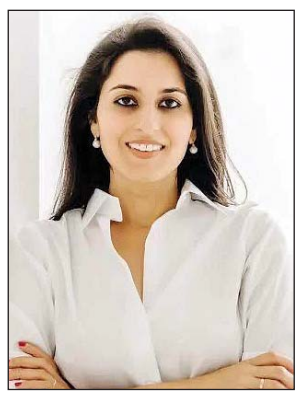
चीन के संबंध में ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने राजनीतिक समर्थन बनाए रखने के लिए उसके जहाजों को

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जयपुर की पिया डांडिया अमेरिका में निर्वाचित

-प्रकाश भण्डारी-

जयपुर, 4 नवम्बर। गुलाबी शहर की बेटी पिया डांडिया अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रैज़ैन्टेटिव्स की सदस्य बन गई



हैं। डैमोक्रैट पार्टी की उम्मीदवार के रुप में पिया ने फ्लोरिडा राज्य के बाईसवें कांग्रेसनल जिले से जीत दर्ज करके इतिहास रचा है। पिया ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार केसी अस्कर को पराजित कर दिया।

पिया डांडिया जयपुर के ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से सम्बंधित हैं, जो शिक्षा और पत्रकारिता तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। पिया, डॉ. रोहित और भारती डांडिया की पुत्री हैं जो 40 वर्ष पूर्व अमेरिका में जा बसे थे। पिया विश्व प्रसिद्ध

(शेष पृष्ठ 6 पर)

'कई साल पहले जब मैंने पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, तब सभी विपक्षी दलों ने मुझ पर कटाक्ष किया था'

'अब सभी दल यह स्वीकार कर रहे हैं कि ड्रग्स पंजाब की एक बड़ी समस्या बन चुकी है'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पंजाब में "इंसाफ रैली" के जरिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा और राज्य में नशे की समस्या, खासकर "चिट्टा" को बड़ा मुद्दा बताया। इस दौरान दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ अपनी मुलाकात को याद कर उन्होंने लोगों से भावनात्मक जुड़ाव भी बनाया।

संगरूर जिले के फग्गूवाला गांव में आयोजित "इन्साफ रैली" में गांधी ने कहा, "कई साल पहले मैंने कहा था कि पंजाब में नशा फैल रहा है। उस समय भाजपा और अकाली दल ने ड्रग्स के खतरे को तवज्जो न देते हुए, मेरी बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि राहुल गांधी पंजाब के बारे में कुछ नहीं जानते। आज "चिट्टा" (मिलावटी हेरोइन) राज्य की एक बड़ी समस्या बन चुका है।" इस रैली के जरिए, उन्होंने अगले साल के शुरु में होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव-प्रचार का बिगुल बजा दिया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो पंजाब के लिए काम करे, "आप" सरकार जैसी नहीं, जो दिल्ली से चलाई जाती हो।

राहुल ने भीड़ से पूछा, "बताइए, आम आदमी पार्टी ने अपने कौन-से चुनावी वादे पूरे किए हैं?" उन्होंने लोगों से रोजगार और नशामुक्त पंजाब के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की।

रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह और राज्य के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा, विजय इंदर सिंगला, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजिंदर कौर भट्टल तथा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग मौजूद थे।

गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दी गई अपनी चुनौती को दोहराया। कांग्रेस को देशविरोधी बताने के आरोप को लेकर उन्होंने मोदी को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा, "कहीं भी आ जाइए, मेरे साथ बैठिए और बहस कीजिए।"

भाजपा पर हमला करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने संसद में बहस कराने के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा, "वे कहते हैं कि संसद में चर्चा करिए, लेकिन आप मेरा माइक बंद कर देते हैं

(शेष पृष्ठ 6 पर)

- संगरूर जिले के फग्गूवाला गाँव में विशाल "इंसाफ रैली" से कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का आगाज़ किया और ड्रग्स के मुद्दे पर राज्य व केन्द्र सरकार पर करारा हमला बोला।
- रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह, अन्य वरिष्ठ नेता, जैसे प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आदि शामिल हुए।
- गांधी ने जनता से भावात्मक जुड़ाव के लिए अपने भाषण में पंजाब के विख्यात गायक सिद्धू मूसेवाला से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया।

पूर्व विधायक बलजीत यादव को जमानत मिली

जयपुर, 4 नवंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीद से जुड़े ईडी मामले में पूर्व विधायक बलजीत यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने

- यादव पर 32 सरकारी स्कूलों में खेल साम्रगी खरीद में कथित भ्रष्टाचार का आरोप है

यह आदेश बलजीत यादव की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता चित्रांश सक्सेना ने अदालत को बताया कि प्रकरण में ईडी पूरक आरोप पत्र पेश कर चुकी है। वहीं, अदालत उस पर आरोप भी तय कर चुकी है। ऐसे में अब याचिकाकर्ता से किसी तरह की पूछताछ या अनुसंधान बाकी नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग

(शेष पृष्ठ 6 पर)

अमेरिका के मिड टर्म चुनाव नतीजों ने दुनिया भर में राजनैतिक हड़कम्प पैदा किया

यूरोपियन नेता और भारत, चीन, रूस सहित सभी देश अपने-अपने हिसाब से इन चुनाव नतीजों का आकलन कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि वॉशिंगटन में बदलते सत्ता संतुलन का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ेगा।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 नवम्बर। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत से दुनिया भर में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यूरोपीय नेताओं ने इस नतीजे का स्वागत करते हुए इसे दक्षिणपंथी लोकलुभावन (राइट विंग पॉपुलिज़्म) राजनीति के लिए एक झटका बताया है। भारत इसके व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रहा है, जबकि अमेरिका के प्रमुख भू-राजनीतिक (जिओपोलिटिकल) प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस इस बात पर सावधानी बरत रहे हैं कि वॉशिंगटन में बदले हुए पावर बैलेंस का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर हो सकता है।

सीनेट हाउस ऑफ रिप्रैज़ेन्टेटिव्ज़, दोनों पर डेमोक्रेट्स का कब्ज़ा, साथ ही परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत गढ़ों में भी जीत, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चुनावी झटका है। इन नतीजों से उम्मीद है कि कांग्रेस उनके प्रशासन की, खासकर व्यापार, इमिग्रेशन और विदेश नीति पर, जांच तेज करेगी, हालांकि, ट्रंप के पास अब भी काफी एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स हैं।

वॉशिंगटन के साथ संबंध रखने वाले देशों के लिए इन नतीजों से नए अवसर भी पैदा हुए हैं और अनिश्चितताएं भी बढ़ी हैं। डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस राष्ट्रपति के फैसलों पर अधिक रोक लगा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी नीतियां तुरंत बदल जाएंगी।

नई दिल्ली में इन नतीजों पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि इनका द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स के नियंत्रण से भारत को वॉशिंगटन के साथ बातचीत में कुछ राहत मिल सकती है। खासकर ट्रंप की आयात शुल्क संबंधी नीतियों और प्रस्तावित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर।

एडमिनिस्ट्रेश के ट्रेड संबंधी फैसलों पर कांग्रेस की अधिक जांच से कुछ एकतरफा कदमों पर रोक लग सकती है। हालांकि, व्यापार और विदेश नीति के मामलों में ट्रंप के पास अब भी काफी अधिकार हैं। इसलिए नई दिल्ली को आर्थिक दबावों में तुरंत कमी आने की उम्मीद नहीं है।

इस मामले में काफी कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, आयात शुल्क, ऊर्जा की खरीद और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं।

इन नतीजों का भारत के टैक्नोलॉजी सैक्टर और स्किल्ड प्रोफैशनल्स पर भी असर पड़ सकता है, खासकर ट्रंप प्रशासन के एच-1बी वीजा प्रोग्राम को और सख्त करने की कोशिशों के बीच, जिसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफैशनल्स और टैक्नोलॉजी कंपनियां करती हैं।

नई दिल्ली का व्यापक रुख व्यावहारिक बने रहने की संभावना है। अमेरिकी कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलने से बातचीत और सहयोग के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप

(शेष पृष्ठ 6 पर)

- अमेरिका के मिड टर्म चुनावों में डैमोक्रैट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रैज़ैन्टेटिव्स पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, यही नहीं रिपब्लिकन पार्टी का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भी डैमोक्रैट्स जीते हैं।
- वॉशिंगटन से डील कर रहे देशों के लिए इन नतीज़ों से अनिश्चितता भी बढ़ी है, साथ ही नए अवसर भी पैदा हुए हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने निर्णयों पर अंकुश लगा सकती है।

लद्दाख में खाई में गिरा सेना का वाहन, दो जवानों की मौत

लेह, 04 नवंबर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग-01 पर नामिका ला दर्रे के पास बुधवार, 4 नवंबर को सेना का एक भारी वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में वाहन में सवार भारतीय सेना के दो जवान, चालक और सह चालक की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। गहरी खाई से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों जवानों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), चिकतान पहुंचाया गया।